



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 1987/चैत्र 18, 1909

No. 170] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 1987/CHAITRA 18, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली 8 अप्रैल, 1987

आदेश

का. आ. 330 (अ):—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 641 (अ), तारीख 10 नवम्बर 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) वेस्ट बंगाल कार्पासियटिकल एंड फाइबर कैमिकल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., इलाकी हाउस, (दूसरी मंजिल) 1 और 2 बार्बोन रोड, कलकत्ता-700001 की (जिने इसमें इसके पश्चात् उक्त, प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), मैसर्स डा. पाल लोहमैन (इंडिया) लि., कलकत्ता नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रवन्ध 10 नवम्बर, 1978 से प्रारम्भ होने वाली अवधि से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं. का. अस. 793 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 1981, सं. का. आ. 312 (अ) तारीख 8 मई, 1982 सं. का. आ.

789 (अ) तारीख 9 नवम्बर, 1982, सं. का. आ. 801 (अ) तारीख 10 नवम्बर, 1983, सं. का. आ. 364 (अ) तारीख 8 मई, 1984 सं. का. आ. 825 (अ) तारीख 9 नवम्बर, 1984, सं. का. आ. 926 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1984 और सं. का. आ. 104 (अ) तारीख 8 फरवरी, 1985 और सं. का. आ. 596 (अ) तारीख 8 अगस्त 1985, सं. का. आ. 730 (अ) तारीख 8 अक्टूबर, 1985, सं. का. आ. 180 (अ) तारीख 9 अप्रैल, 1986, सं. का. आ. 205 (अ) तारीख 23 अप्रैल, 1986, सं. का. आ. 247 (अ) तारीख 8 मई, 1986 सं. का. आ. 303 (अ) दिनांक 26 मई, 1986 और सं. का. आ. 344 (अ) दिनांक 6 जून, 1986 सं. का. आ. 368 (अ) दिनांक 19 जून, 1986, सं. का. आ. 410 (अ) दिनांक 8 जुलाई, 1986, सं. का. आ. 419 (अ) दिनांक 11 जुलाई, 1986, सं. का. आ. 434 (अ) दिनांक 8 अगस्त, 1985 और का. आ. 734 (अ) तारीख 8 अक्टूबर, 1986 द्वारा उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय को अनुज्ञा से उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रवन्ध 8 अप्रैल, 1987 तक, जिसमें यह तारीख सम्मिलित है आठ वर्ष और पांच माह की अवधि के लिए करने रहने के लिए समय-समय पर निदेश दिए थे।

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि जन साधारण के हित में समीचीन था कि उक्त प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध आठ वर्ष पांच माह की समिति की अवधि के पश्चात् करता रहे उक्त अधिनियम की धारा 18 बक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन बलवत्ता उच्च न्यायालय को आवेदन किया था और उससे ऐसे प्रबन्ध को छह माह की और अवधि के लिए बनाए रखने की प्रार्थना की थी।

और उक्त उच्चन्यायालय के अपने आदेश तारीख 6 अप्रैल, 1987 द्वारा उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 6 माह और अवधि के लिए करते रहने की अनुज्ञा दी थी।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 बक उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रयत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेदन देती है कि उक्त आदेश छ. माह तक की, जिसमें 8 अक्टूबर 1987 की तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फाइल नं. 4(2)/80-सी.यू.एम.]

ए. वी. गोकक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 8th April, 1987

ORDER

S.O. 330(E).—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 641(E), dated the 10th November, 1978 (hereinafter referred to as the said order); the Central Government had authorised the West Bengal Pharmaceutical and Phytochemical Development Corporation Limited, ILaco House (2nd Floor), 1 and 2, Brobourn Road Calcutta-70001. (hereinafter referred to as the said authorised person) to take over the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs Dr. Paul Lohmann (India) Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of three years commencing on the 10th November, 1978;

And, whereas, by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 793(E), dated the

9th November, 1981, S.O. 312(E), dated the 8th May, 1982, S.O. 789(E), dated the 9th November, 1982, S.O. 801(E), dated the 10th November, 1983, S.O. 364(E), dated the 8th May, 1984, S.O. 825(E) dated the 9th November, 1984, S.O. 926(E) dated the 7th December, 1984, S.O. 104(E) dated the 8th February, 1985, S.O. 596(E), dated the 8th August, 1985, S.O. 730(E), dated the 8th October, 1985, S.O. 180(E), dated the 9th April, 1986, S.O. 205(E) dated 23rd April 1986, S.O. 247(E), dated the 8th May, 1986, S.O. 303 (E), dated 26th May, 1986, S.O. 344(E), dated the 6th June, 1986, S.O. 368(E) dated 19th June, 1986, S.O. 410(E), dated 8th July 1986, S.O. 419(E) dated 11th July, 1986, S.O. 484 (E), dated 8th August, 1986 and S.O. 734(E) dated 8th October, 1986, the Central Government with the permission of the High Court at Calcutta under Section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) had from time to time directed the said authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a period of eight years and five months upto and inclusive of the 8th April, 1987.

And, whereas the Central Government being of the opinion that it was expedient in the interest of the general public that the said, authorised person should continue to manage the said industrial undertaking after the expiry of the said period of eight years and five months made and application under the proviso to sub-section (2) of the section 18FA of the said Act to the High Court at Calcutta praying for the continuance of such management for a further period of six months.

And, whereas the said High Court, by its order dated 6th April, 1987, permitted the said authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 8th October, 1987

[File No. 4(2)/80-CUS]

A. V. GOKAK, Jt. Secy.